भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †1932
31 जुलाई, 2025 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए अवसंरचना और निवेश सहायता

†1932. श्री नवीन जिंदल:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भारत की वैश्विक अग्रणी स्थिति को मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से किसानों को सहायता प्रदान करने और कृषि उत्पादों के मूल्य को बढ़ाने के लिए क्या प्रमुख पहल की गई है;

(ग) फलों, सब्जियों और बाजरा के अग्रणी उत्पादक के रूप में भारत की स्थिति ने उक्त वृद्धि में कितना योगदान दिया है;

(घ) क्या हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र की निर्यात क्षमता और रोजगार के अवसरों में वृद्धि देखी गई है और यदि हॉं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए मेक इन इंडिया अभियान के अंतर्गत अवसंरचना और निवेश सहायता का विस्तार करने की योजना बना रही है और यदि हॉं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) लागू कर रहा है। यह योजना 2021-22 से 2026-27 तक छह वर्षों की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कार्यान्वित की जा रही है।

भारतीय खाद्य उत्पादों में निवेश और सोर्सिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2017, 2023 और 2024 के दौरान वर्ल्ड फूड इंडिया(डब्ल्यूएफआई) के तीन संस्करणों का आयोजन किया था, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में उनके एकीकरण की सुविधा प्रदान करके खाद्य प्रसंस्करण में निवेश के अवसरों और प्रगति को उजागर करने के लिए एक प्रमुख मंच प्रदान करता है। यह आयोजन वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों, नवप्रवर्तकों, आपूर्ति श्रृंखला हितधारकों, उपकरण निर्माताओं आदि को एक सहयोगी मंच पर लाता है और विदेशी कंपनियों को अपने भारतीय समकक्षों के साथ गठजोड़/व्यावसायिक अवसर प्रदान करता है।

(ग) और (घ): भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में तेजी से बदलाव आया है, जो इसके विशाल कृषि आधार, बढ़ती घरेलू मांग और सहायक सरकारी नीतियों से प्रेरित है। भारत एक प्रभावशाली विकास प्रक्षेपवक्र के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरने के लिए तैयार है। कृषि क्षेत्र भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की रीढ़ है, कृषि सांख्यिकी एक नज़र, 2023 के अनुसार भारत फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा, एमओएफ़पीआई ने रेडी टू कुक (टीआरसी) / रेडी टू ईट (आरटीई) उत्पादों में मिलेट के उपयोग को प्रोत्साहित करने और खाद्य उत्पादों में मिलेट के उपयोग को बढ़ाने और मूल्यवर्धन और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए मिलेट आधारित उत्पादों (पीएलआईएसएमबीपी) के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत उन्हें प्रोत्साहित करने की पहल की। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र जीडीपी, रोजगार और निर्यात में अपने योगदान के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण खंड बनकर उभरा है। वित्त

वर्ष 2024-25 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात लगभग 49.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात का हिस्सा लगभग 20.4% है। इसके अलावा, प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात में हिस्सेदारी 2014-15 के 13.7% से बढ़कर 2024-25 में 20.4% हो गई है। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, 2022-23 के अनुसार, पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में लगभग 2.23 मिलियन श्रमिक कार्यरत हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण, 2023-24 के अनुसार, अपंजीकृत क्षेत्र में 4.68 मिलियन श्रमिक कार्यरत हैं।

(ङ): विनिर्माण को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से, सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान के तहत फसलोपरांत बुनियादी ढांचे के विकास और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं के साथ-साथ कई सुधार और नीतिगत उपाय शुरू किए हैं:-

(i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में पहले स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति थी। 2016-17 में, भारत में निर्मित और/या उत्पादित खाद्य उत्पादों के संबंध में ई-कॉमर्स के माध्यम सहित व्यापार के लिए सरकारी अनुमोदन मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई थी।
(ii) बजट 2014-15 में की गई घोषणा के अनुसार, नामित खाद्य पार्कों और इन पार्कों में स्थापित की जाने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में किफायती ऋण उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड में 2,000 करोड़ रुपये का एक विशेष कोष स्थापित किया गया है।
(iii) कारोबार में आसानी के संबंध में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय "प्रस्ताव प्राप्त करने से लेकर सहायता अनुदान जारी करने तक" पूरी तरह से ऑनलाइन योजना प्रबंधन प्रणाली पर काम कर रहा है।
(iv) इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश भर में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना नामक केंद्रीय क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से , रोजगार के अवसरों के सृजन, कृषि उपज की बर्बादी को कम करने, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रचार, समग्र विकास और वृद्धि के लिए खेत से खुदरा दुकान तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करता है।
(v) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए तकनीकी, वित्तीय और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना-पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना को भी लागू कर रहा है।

*****